International Day of Forests

अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस
21 मार्च 2017

22 MARCH WORLD WATER DAY

विश्व जल दिवस
22 मार्च 2017

के उपलक्ष्य में

जल—जंगल—नर्मदा—भोपाल

की थीम पर आधारित

समग्र शासन की ओर जागरूकता अभियान

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन

International Day of Forests

The International Day of Forests is celebrated on 21 March every year. It's an opportunity to raise awareness of the importance of all types of forests and trees. The Day was established by the UN General Assembly in 2012. Activities range from scientific conferences and workshops, to art exhibits, tree planting and community-level events. The theme of the International Day reflects the multi-faceted aspects of forests, highlighting the many ways forests contribute to our daily lives and global sustainability. Theme for World Forestry Day 2017 is “Forests & Energy”.

UN WATER

22 MARCH WORLD WATER DAY

World Water Day is marked on 22 March every year to celebrate water and focus attention on the importance of freshwater and addressing water related challenges. In 1993, the UN General Assembly designated 22 March as the first World Water Day. Today, World Water Day is celebrated around the world; coordinated by UN-Water, the topic of the annual campaign rotates each year in alignment with the UN World Water Development Report (WWDR). World Water Day, on 22 March every year, is about taking action on water issues. The theme for World Water Day 2017 is 'Wastewater' and the campaign, 'Why waste water?' is about reducing and reusing wastewater.

नमामि देवि नर्मदे

नर्मदा नदी केवल नदी मात्र ही नही अपितु आस्था व विश्वास का प्रतीक है, यह प्रदेश वासियों के लिए जीवनदायिनी नदी है, इसलिए इसके जल का निर्मल एवं अविरल बहते रहना अत्यंत आवश्यक है, इसका संरक्षण किया जाना जरूरी है। वर्तमान मे प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण शहरों की पेयजल की आपूर्ति नर्मदा से जुडा है। इस संबंध में शहरवासियों को समझ बढाना होगा एवं वनाच्छादित नदी कछारों की संरक्षण में हाथ बंटाना होगा।

सतत विकास लक्ष्य 2030

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

6 CLEAN WATER AND SANITATION

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।

13 CLIMATE ACTION

जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना।

15 LIFE ON LAND

स्थलीय पारिस्थिकी तंत्रों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों की सतत तरीके से प्रबंधन करना, मरूस्थल–रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैवविविधता की हानि को रोकना।

जल–जंगल–नर्मदा–भोपाल

के परिवेश में

समग्र शासन की अवधारणा

सम्पूर्ण विश्व में 21 मार्च को ''अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस'' एवं 22 मार्च ''विश्व जल दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व वानिकी दिवस की विषयवस्तु ''वन एवं ऊर्जा (Forest and Energy)'' तथा विश्व जल दिवस की विषयवस्तु ''अपशिष्ट जल (Waste Water)'' निर्धारित की गयी है।

वर्तमान में मान. मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में दिनांक 11 दिसम्बर 2016 से ''नर्मदा सेवा यात्रा'' प्रारंभ की गयी है जो दिनांक 11 मई 2017 तक चलेगी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के विकास में नर्मदा नदी के महत्व को रेखांकित करते हुए नर्मदा के प्रवाह को अविरल, प्रबल, निर्मल (प्रदूषण मुक्त) बनाये रखना है। नर्मदा नदी को अविरल बनाने में जंगलों व नर्मदा का निर्मल बनाये रखने में नदी के किनारे बसे शहर एवं गांवो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण शहरों की पेयजल व्यवस्था नर्मदा पर ही निर्भर है।

सिंहस्थ 2016 का विचार महाकुंभ के सार्वभौम अमृत संदेश भी इन्हीं विचारों को रेखांकित की है।

भारत सरकार, नीति आयोग द्वारा अपनाई जा रही सतत् विकास लक्ष्य 2030 (Sustainable Development Goal 2030) में 17 लक्ष्य भी इसी बात को कहते है। स्पष्ट रूप से लक्ष्य क्रमांक 6 (सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना), लक्ष्य 13 (जलवायु परिवर्तन) एवं लक्ष्य 14 (स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण) सतत विकास लक्ष्य इन्हीं बातों का समावेश व सुनिश्चित करने की बात कहते है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमान है कि 2030 तक भारत की 70 प्रतिशत आबादी शहरों में ही बसेगी ऐसी स्थिति में हमारा प्रदेश की भी 70 प्रतिशत आबादी शहरों में ही बसेगी अर्थात प्रदेश के शहरों में रहने वाली आबादी के पेयजल की पूर्ति भी नदियों के ऊपर ही आधारित रहेगी। उल्लेखनीय बात यह है कि नदियों में जल का प्रवाह अविरल व प्रबल बनाये रखने हेतु प्रदेश के जंगलों का स्वास्थ्य सही बनाये रखना आवश्यक है। परंतु इस संबंध में शहरी आबादी की समझ नगण्य है व इस समझ को बढ़ाने की दिशा में सार्थक कदम उठाना आवश्यक है।

पानी का उत्पादन व गुणवत्ता जंगलों पर निर्भर है और शहरों की पेयजल पूर्ति व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन नदियों में जल प्रवाह की निरंतरता व प्रबलता पर निर्भर है। इस दिशा में शहरों में रहने वाली आबादी को जागरूक करना आवश्यक है। अतः इस दिशा में भारत सरकार के सतत विकास लक्ष्य तथा मध्य प्रदेश शासन के ''नमामि देवि नर्मदे'' के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में पेयजल हेतु नर्मदा पर निर्भर शहरों में जन जागरूकता अभियान का आयोजन करने की आवश्यकता है।

सतत विकास लक्ष्य 2030 एवं नमामि देवि नर्मदे के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये जैव संसाधनों का प्रबंधन व उपयोग करने वाले सभी शासकीय/अशासकीय विभाग, संस्थायें तथा आम नागरिकों के साथ जल, जंगल, नर्मदा (नदी) व भोपाल (समुदाय) के अंतर संबंध पर प्रकाश डालते हुए एक समग्र विकास की सोच विकसित करते हुए जागरूकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 19 से 22 मार्च 2017 तक की अवधि में ''जल–जंगल–नर्मदा (नदी) व भोपाल (समुदाय)'' विषयक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

यह कार्यक्रम मात्र एक विभाग का न होकर समग्र शासन से ही संभव है जिसमें प्रजा भी सम्मिलित है। जल–जंगल–नर्मदा–समुदाय की दिशा में शासकीय विभाग/संस्थायें व आम नागरिकों की भागीदारी से ''जल–जंगल–नर्मदा (नदी) व भोपाल (समुदाय)'' विषयक जन जागरूकता अभियान आयोजित है। अर्थात समाज व शासन (शासन के सभी अंग) एक दिशा में लक्ष्य प्राप्ति की ओर कार्य करेंगे।